ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
प्रो. रजनीश जैन
सचिव
**Prof. Rajnish Jain**
**Secretary**

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
**University Grants Commission**
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

273-Gen

D.O. No.1-15/2009 (ARC) pt.III

04 JUL 2019

27th June, 2019

Respected Sir/Madam,

In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 08.05.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the UGC had notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009". The Regulations are available on the UGC website i.e. www.ugc.ac.in. These regulations are mandatory for all higher educational institutions in the country.

As multiple mechanisms are required to ensure a ragging-free campus, here are some recommendations and action steps which are required to be deployed in your esteemed university and all institutions under your ambit.

**A. Basic Measures:**

1. Constitution of anti-ragging committee, anti-ragging squad, setting up of Anti-Ragging Cell and adequate publicity for these measures through various media are to be undertaken.
2. Mention of anti-ragging warning in the institution's prospectus and information booklets /brochures shall be ensured.
3. Updating websites of institutions with the complete address and contact details of nodal officers related to anti-ragging committee.
4. In compliance with the UGC Regulations and its 2nd Amendment regarding submission of undertaking by each student and every parent, an online undertaking in every academic year to be submitted.
5. UGC has notified 3rd Amendment in UGC Regulations on 29th June, 2016 to expand the definition of ragging by including the following:

   *"3. (i) Any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background."*

6. Installing CCTV cameras at vital points.

**B. Counseling and monitoring measures**

1. Regular interaction and counseling with the students can detect early signs of ragging and identification of trouble-triggers.
2. Surprise inspection at hostels, students accommodation, canteens, rest-cum-recreation rooms, toilets, bus-stands and any other measure which would augur well in preventing/quelling ragging and any uncalled for behaviour/incident shall be undertaken.

**C. Creative Dissemination of the idea of ragging-free campus**

1. Events like Anti-Ragging workshops, seminars and other creative avenues to spread the idea.
2. Safety and security apps without affecting the privacy of individuals can be creatively deployed.

Contd...2

President

Registrar
Dat 110765
8-7-19

**D. Using other UGC initiated measures**

1. Students in distress due to ragging related incidents can call the National Anti-Ragging Helpline **1800-180-5522 (24x7 Toll Free)** or e-mail the Anti-Ragging Helpline at helpline@antiragging.in.
2. For any other information regarding ragging, please visit the UGC website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in and contact UGC monitoring agency i.e. Aman Satya Kachroo Trust on mobile No. 09871170303, 09818400116 (only in case of emergency).
1. UGC also drives an Anti-Ragging Media Campaign through different modes and UGC has got developed the following entities to promote anti-ragging which are available on UGC website i.e. www.ugc.ac.in.

   a. UGC has developed 05 TVCs of 30 seconds each from different perspective i.e. Parents, Victim and Offenders.

   b. UGC has designed and distributed posters amongst Universities/Regulatory Authorities/Councils/IITs/NITs/Other educational institutions for the prominent display.

   c. UGC has consecutively organized 02 Anti-Ragging Competitions for students/faculty /general public for the wider awareness of the menace of ragging.

Any violation of UGC Regulations or failure of institution to take adequate steps to prevent ragging in accordance with these Regulations or failure to punish perpetrators of incidents of ragging suitably, will attract punitive action under the UGC Act.

You are requested to implement the recommendations communicated vide this office letter of even number dated December 27, 2018 and thereby ensure a ragging-free campus, a fundamental requirement for a supportive and fair institutional climate which is open to change, learning and progress.

With personal regards,

Yours sincerely,

**(Rajnish Jain)**

**The Vice-Chancellor of all Universities.**

**Copy to :**

The President, Council of Architecture, India Habitat Centre, Core 6A, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi- 110 003----**with a request to take necessary steps to ensure these activities in all the Universities/ Institutions under your ambit.**

**(Rajnish Jain)**
**Secretary**

अर्ध शासकीय पत्र संख्या 1–15/2009(एआरसी) भाग. III दिनांकः 21 जून, 2019

आदरणीय महोदय/ महोदया,

माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर दिनांक 08 मई, 2009 की सिविल अपील संख्या 887/2009 में दिए गए निर्णय के अनुपालन में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विनियम, 2009" को अधिसूचित किया है। यह विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं। यह विनियम देश के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनिवार्य हैं।

चूंकि रैगिंग मुक्त परिसर सुनिश्चित करने के लिए, बहु प्रणालियों की आवश्यकता है, आपके क्षेत्राधिकार के तहत आपके सम्मानित विश्वविद्यालय तथा सभी संस्थानों में लागू किए जाने वाली कुछ सिफारिशों तथा कार्रवाईयों का ब्योरा नीचे दिया गया है।

क. मूलभूत उपायः

1. रैगिंग रोधी समितियों, रैगिंग रोधी दस्तों का गठन, रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना और विभिन्न मीडिया के माध्यम से इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए।

2. संस्थान की विवरणिका और सूचना पुस्तिकाओं/ ब्रोशर में रैगिंग रोधी चेतावनी का उल्लेख सुनिश्चित किया जाएगा।

3. रैगिंग रोधी समिति से संबंधित नोडल अधिकारियों के पूर्ण पते और संपर्क संबंधी ब्योरे के साथ संस्थानों की वेबसाइट अद्यतन करना।

4. प्रत्येक छात्र और प्रत्येक माता–पिता द्वारा वचनपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों तथा इसके द्वितीय संशोधन के अनुपालन में प्रत्येक शिक्षा वर्ष में एक ऑनलाइन वचनपत्र जमा करना होगा।

5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत को शामिल करते हुए रैगिंग की परिभाषा को विस्तार देने के लिए दिनांक 29 जून, 2019 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों में तीसरे संशोधन को अधिसूचित किया:

*"3. किसी दूसरे छात्र (नए अथवा अन्यथा) पर रंग, नस्ल, धर्म, जाति, नृजातीय, लिंग (ट्रांसजेंडर सहित), यौन झुकाव, रूपरंग, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीयता, भाषायी पहचान, जन्म स्थान, निवास स्थान अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर शारीरिक अथवा मानसिक दुर्व्यवहार (जिसमें दबंगई तथा बहिष्करण शामिल है) का कोई भी कृत्य"*

6. महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना।

**ख. परामर्श तथा निगरानी संबंधी उपाय**

1. छात्रों के साथ नियमित रूप से बातचीत और परामर्श से रैगिंग के शुरुआती लक्षणों और समस्याओं को पैदा करने वाले अन्य कारकों की पहचान की जा सकती है।

2. छात्रावासों, छात्रों के आवास, जलपानगृह, विश्राम–सह–मनोरंजन कक्ष, शौचालयों, बस–स्टैंड का औचक निरीक्षण, और कोई भी अन्य उपाय जो रैगिंग को रोकने/ लगाम लगाने और अनुचित व्यवहार/ घटना के रोकने में प्रभावी साबित होंगे।

**ग. रैगिंग मुक्त कैम्पस के विचार का सृजनात्मक रूप से प्रसार**

1. विचार के प्रसार के लिए रैगिंग रोधी कार्यशालाएं, संगोष्ठियां जैसे कार्यक्रम और अन्य रचनात्मक उपाय करना।
2. व्यक्तियों की गोपनीयता को प्रभावित किए बिना सुरक्षा और संरक्षा ऐप रचनात्मक रूप से तैनात किए जा सकते हैं।

**घ. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आरंभ किए गए अन्य उपायों का उपयोग करना**

1. रैगिंग संबंधित घटनाओं के कारण परेशान छात्र राष्ट्रीय रैगिंग रोधी हेल्पलाइन नम्बर 1800–180–5522 (24 X 7 टोल निःशुल्क) पर कॉल कर सकते हैं अथवा हेल्पलाइन helpline@antiragging.in पर रैगिंग रोधी हेल्पलाइन पर ई–मेल कर सकते हैं।

2. रैगिंग के संबंध में किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.ugc.ac.in और www.antiragging.in पर जाएं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निगरानी एजेंसी अर्थात् अमन सत्य कचरू ट्रस्ट से मोबाइल नंबर 09871170303, 098184116 (केवल आपात स्थिति में) पर संपर्क करें।

09818400116